

अध्याय-V: राज्य आबकारी

5.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व), राज्य आबकारी विभाग (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख हैं। आबकारी आयुक्त, विभाग के प्रमुख हैं। विभाग सात संभागों में विभक्त है जिनके प्रमुख अतिरिक्त आबकारी आयुक्त हैं। जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक, आबकारी शुल्क एवं अन्य शुल्कों के आरोपण/संग्रहण की देखरेख तथा नियंत्रण का कार्य सम्बंधित संभागों के अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों के नियंत्रणाधीन करते हैं।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य आबकारी विभाग में कुल 108 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ (54 कार्यान्वयन इकाइयों समेत) हैं, जिनमें से लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा करने के लिए 32 इकाइयों (20 कार्यान्वयन इकाइयों सहित) का चयन किया गया। इन इकाइयों के अभिलेखों, जिनमें 4,925 खुदरा अनुज्ञाधारी (कुल 5,952 अनुज्ञाधारियों में से) सम्मिलित है, की संवीक्षा 11,646 प्रकरणों की जांच के साथ की गई। लेखापरीक्षा में 6,797 प्रकरणों में (लगभग 58 प्रतिशत) राशि ₹ 512.38 करोड़ के आबकारी शुल्क, अनुज्ञापत्र शुल्क, अतिरिक्त राशि की अवसूली/कम वसूली, विलम्ब से भुगतान पर ब्याज/जुर्माना की अवसूली, प्रासव/मदिरा/बीयर की अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क की हानि और अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं। चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जांच पर आधारित ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं। समान प्रकृति की कमियां लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व के वर्षों में भी ध्यान में लायी गयी थी। तथापि, ये अनियमितताएं न केवल बनी रहीं अपितु इनमें से कुछ आगामी लेखापरीक्षा होने तक पहचानी नहीं जा सकी।

पायी गई अनियमितताएं मुख्यतः नीचे दी गयी तालिका 5.1 में निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

तालिका 5.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	आबकारी शुल्क और अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली /कम वसूली।	4,693	500.87
2	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर पर अतिरिक्त राशि की अवसूली/कम वसूली	254	5.89
3	प्रासव/मदिरा/बीयर की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि।	07	0.10
4	विलंब से भुगतान पर ब्याज/जुर्माना की अवसूली।	354	5.52
5	अन्य अनियमितताएं:		
	(i) राजस्व	1,489	0.00
	(ii) व्यय	0	0.00
	योग	6,797	512.38

विभाग ने 6,197 प्रकरणों में निहित राशि ₹502.28 करोड़ की अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 499.73 करोड़ के 5,030 प्रकरण वर्ष 2022-23 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों

में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। विभाग द्वारा 1,178 प्रकरणों में ₹ 2.68 करोड़ की राशि वसूली की गई, जिनमें से ₹ 0.15 करोड़ के 13 प्रकरण वर्ष 2022-23 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे।

राज्य सरकार ने स्वीकार किया (सितंबर 2023) तथा जिला आबकारी अधिकारी, अलवर के अधिकार क्षेत्र में स्थित एक ब्रेवरी पर अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली से संबंधित एक प्रकरण में ₹ 20 लाख की राशि को पूर्ण रूप से वसूल किया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने स्वीकार किया (मई 2024) तथा बीयर की थोक बिक्री के अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली से संबंधित दो प्रकरणों (जिला आबकारी अधिकारी बहरोड़ से संबंधित) में ₹ 14.00 लाख की राशि को पूर्ण रूप से वसूल किया। इस प्रतिवेदन में इन अनुच्छेदों पर चर्चा नहीं की गई है।

विभाग की लेखापरीक्षित इकाइयों में पाये गये ₹ 247.72 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकतर मामले पूर्व में भी उठाए गए थे एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पूर्ववर्ती वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित हुए जिनमें सरकार ने आक्षेपों को स्वीकार कर कार्यवाही/वसूली प्रारंभ की। तथापि, यह देखा गया कि विभाग ने मात्र उन्हीं मामलों में कार्यवाही की जो कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए तथा विभाग आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ नहीं किया जिससे समान प्रकृति के प्रकरणों की आगामी वर्षों में पुनरावृत्ति हुई।

5.3 भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल) और बीयर की कम उठाई गई मात्रा पर अतिरिक्त राशि की अवसूली

राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति (नीति) 2017-19 से 2020-21 के अनुसार, 2020-21 के दौरान भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल) की कम उठाई गई मात्रा पर ₹ 20 प्रति बल्क लीटर (बीएल) की दर से और बीयर की कम उठाई गई मात्रा पर ₹ 10 प्रति बीएल की दर से अतिरिक्त राशि का शुल्क त्रैमासिक रूप से ऐसे रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों से लिया जाना था जिन्होंने पिछले वर्ष की इसी तिमाही में ली गई मात्रा की तुलना में चालू वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान आईएमएफएल और बीयर का उठाव न्यूनतम 10 प्रतिशत तक नहीं बढ़ाया था। यह प्रावधान 2019-20 तक रिटेल ऑन अनुज्ञाधारियों पर भी लागू था, तथापि, 2020-21 की नीति में रिटेल ऑन अनुज्ञाधारियों के लिए उठाव वृद्धि की यह सीमा संशोधित कर 5 प्रतिशत कर दी गई। इसके बाद, कोविड महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने (जुलाई 2020) इस प्रावधान में यह छूट दी कि यदि पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत तक कम मदिरा उठाई गई हो, तो रिटेल ऑन अनुज्ञाधारियों से कोई जुर्माना नहीं वसूला जाएगा।

इसके अलावा, आबकारी आयुक्त ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए (फरवरी 2020) कि प्रत्येक तिमाही के बाद दुकानवार कम उठाई गई मात्रा की गणना करने का प्रावधान विभागीय वेबसाइट/एकीकृत आबकारी प्रबंधन प्रणाली (आईईएमएस) पर उपलब्ध हो, और प्रत्येक तिमाही के अंत में देय अतिरिक्त राशि के भुगतान के बाद ही किसी समूह/दुकान को अगला परमिट जारी किया जाए। यह भी निर्देशित किया गया था कि समय पर राजस्व वसूली सुनिश्चित करने हेतु आई.टी. अनुभाग आवश्यक प्रावधान करें।

अगस्त 2022 से जनवरी 2023 के मध्य चार जिला आबकारी अधिकारियों¹ के कार्यालयों के वर्ष 2016-22 की अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 2018-21 के दौरान, 503 अनुज्ञाधारियों में से 254 अनुज्ञाधारियों ने पिछले वर्ष की संबंधित तिमाही की तुलना में निर्धारित स्तर तक आईएमएफएल और बीयर के उठाव में वृद्धि नहीं की और इस प्रकार वे ₹ 9.75 करोड़ की अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। इस कमी में से, ₹ 3.91 करोड़ की राशि अनुज्ञाधारियों की जमानत राशि से वसूल/समायोजित कर ली गई, तथापि शेष ₹ 5.84 करोड़ की राशि की वसूली विभाग नहीं कर सका। अतः नीति प्रावधानों को लागू करने तथा आबकारी आयुक्त के मौजूदा निर्देशों का पालन करने में विफलता के कारण ₹ 5.84 करोड़ की अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं हो सकी।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2024)। राज्य सरकार ने (सितंबर 2024) जवाब दिया कि ₹ 1.13 करोड़ की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा, जिला आबकारी अधिकारी, डूंगरपुर के संबंध में यह बताया गया कि ₹ 4.65 करोड़ में से ₹ 2.21 करोड़ की राशि वसूली योग्य नहीं है, क्योंकि मदिरा की कम उठाई गयी मात्रा की अतिरिक्त राशि की गणना दुकान के बजाय समूहवार की जानी थी और यदि समूह में एक से अधिक दुकाने हैं, तो मदिरा की कम उठाई गयी मात्रा की अतिरिक्त राशि की गणना समूहवार की जायेगी। उत्तर स्वीकार नहीं है, क्योंकि नीति के प्रावधानों के साथ आबकारी आयुक्त के निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कम उठाई गयी मदिरा की मात्रा पर अतिरिक्त राशि की गणना दुकानवार की जानी थी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

5.4 मासिक गारंटी राशि की कम वसूली

राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति (नीति) 2019-20 एवं 2020-21 के अनुसार देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा के समूह/दुकानवार अनुज्ञापत्र एकाकी विशेषाधिकार राशि (ईपीए)² के आधार पर आवंटित किए गए थे। अनुज्ञाधारी को अपने अनुज्ञापत्र अवधि के लिए निर्धारित ईपीए की राशि देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा पर आबकारी शुल्क के रूप में जमा करनी थी। इसके अलावा, खुदरा बिक्री अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार, अनुज्ञाधारी को संबंधित वर्ष के लिए निर्धारित समूह/दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक ईपीए का भुगतान 12 समान मासिक किश्तों में करना आवश्यक था। मासिक किश्त का भुगतान उस माह की अंतिम तारीख तक करना था। यदि कोई अनुज्ञाधारी देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा का न्यूनतम मासिक कोटा उठाने में असमर्थ रहता है, तो वह आबकारी शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान नकद में करने के लिए उत्तरदायी था।

1 जिला आबकारी अधिकारी: चुरु, धौलपुर, डूंगरपुर और जालोर।

2 ईपीए: निर्दिष्ट क्षेत्र में मदिरा के व्यापार के विशेष अधिकार के लिए देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा समूहों/दुकानों से आबकारी विभाग द्वारा वसूली जाने वाली राशि को ईपीए कहा जाता है।

छ: जिला आबकारी अधिकारियों³ के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2019-21⁴ के दौरान कुल 1,058 अनुज्ञाधारियों ने संबंधित महीनों के लिए निर्धारित कोटा ₹ 481.06 करोड़ के समक्ष ₹ 455.31 करोड़ मूल्य की देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा का उठाव किया जिससे 607 अनुज्ञाधारियों की मासिक गारंटी राशि में ₹ 25.75 करोड़ की कमी रही। इस कमी में से ₹ 13.99 करोड़ की राशि अनुज्ञाधारियों की जमानत राशि से वसूल/समायोजित कर ली गई। तथापि, विभाग शेष ₹ 11.76 करोड़ की राशि 388 अनुज्ञाधारियों से वसूल नहीं कर सका। अतः नीति के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू न करने के कारण ₹ 11.76 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2024)। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए जवाब दिया (अगस्त एवं सितंबर 2024) कि ₹ 2.12 करोड़ की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

5.5 देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की कम उठाई गई मात्रा पर बेसिक लाइसेंस फीस की कम वसूली

राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति (नीति) 2020-21 एवं देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की खुदरा बिक्री अनुज्ञापत्र की शर्तों तथा आबकारी आयुक्त द्वारा फरवरी 2020 एवं फरवरी 2021 में जारी निर्देशों के अनुसार, देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा समूहों के अनुज्ञाधारियों को मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि (ईपीए) का न्यूनतम 30 प्रतिशत 25 यूपी⁵ राजस्थान निर्मित मदिरा के उठाव से और शेष 70 प्रतिशत देशी मदिरा के उठाव से पूर्ण करना आवश्यक था। इसमें से न्यूनतम 40 प्रतिशत मात्रा 50/60 यूपी देशी मदिरा की होनी चाहिए तथा शेष 60 प्रतिशत मात्रा 5 यूपी से 40 यूपी तक की देशी मदिरा की होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त निर्देशों के अनुसार, यदि कोई अनुज्ञाधारी किसी माह विशेष में राजस्थान निर्मित मदिरा और 50/60 यूपी देशी मदिरा के निर्धारित गारंटी अनुपात को पूर्ण करने में असफल रहता है, तो उसे सम्बन्धित तिमाही के अन्य माहों में राजस्थान निर्मित मदिरा और 50/60 यूपी देशी मदिरा का उठाव इस प्रकार सुनिश्चित करना होगा कि कुल तिमाही ईपीए की 30 प्रतिशत गारंटी राजस्थान निर्मित मदिरा के आबकारी शुल्क से, 28 प्रतिशत गारंटी 50/60 यूपी देशी मदिरा से और शेष 42 प्रतिशत गारंटी 5 यूपी से 40 यूपी देशी मदिरा से पूर्ण हो। किसी तिमाही में राजस्थान निर्मित मदिरा एवं 50/60 यूपी देशी मदिरा के निर्धारित 30 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत से कम उठाव के मामले में अनुज्ञाधारी राजस्थान निर्मित मदिरा एवं 50/60 यूपी

3 जिला आबकारी अधिकारी चूरू, डूंगरपुर, जालोर (अगस्त 2022 से जनवरी 2023 के मध्य), बारां, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर (अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के मध्य)।

4 जिला आबकारी अधिकारी चूरू, डूंगरपुर (2019-20 और 2020-21), जालोर, बारां, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर (2020-21)।

5 यूपी 'अंडर प्रूफ' को संदर्भित करता है। यह एक अल्कोहलिक पेय में अल्कोहल की मात्रा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, 50 डिग्री प्रूफ को 50 यूपी तथा 40 डिग्री प्रूफ को 60 यूपी के रूप में दर्शाया जा सकता है।

मदिरा के निर्धारित कोटे व वास्तविक उठाव पर देय आबकारी शुल्क व बेसिक लाइसेंस फीस के अंतर की राशि नकद में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

सात जिला आबकारी अधिकारियों⁶ के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान, 913 अनुज्ञाधारियों ने संबंधित तिमाही में निर्धारित कोटा 112.89 लाख बल्क लीटर राजस्थान निर्मित मदिरा और 158.04 लाख बल्क लीटर 50/60 यूपी देशी मदिरा के समक्ष केवल 105.84 लाख बल्क लीटर राजस्थान निर्मित मदिरा और 153.78 लाख बल्क लीटर 50/60 यूपी देशी मदिरा का उठाव किया। इस कारण तिमाही गारंटी कोटा में 7.05 लाख बल्क लीटर राजस्थान निर्मित मदिरा और 4.26 लाख बल्क लीटर 50/60 यूपी देशी मदिरा की कमी रही, जिस पर 591 अनुज्ञाधारियों से ₹437.54 लाख की बेसिक लाइसेंस फीस की वसूली की जानी थी। इसमें से ₹74.42 लाख की राशि अनुज्ञाधारियों की जमानत राशि से वसूल/समायोजित की गई, तथापि, विभाग शेष ₹363.12 लाख की राशि 456 अनुज्ञाधारियों से वसूल नहीं कर सका। अतः नीति के प्रावधानों को लागू करने में कार्रवाई न करने के कारण ₹363.12 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई-अगस्त 2024)। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अगस्त-सितंबर 2024) बताया कि ₹22.38 लाख की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

5.6 देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा पर आबकारी शुल्क के अंतर राशि की अवसूली

राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति (नीति) 2019-20 तथा देशी मदिरा की खुदरा बिक्री अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार, देशी मदिरा समूहों के अनुज्ञाधारी को मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि (ईपीए) का 40 प्रतिशत, 50/60 यूपी देशी मदिरा की उठाई गई मात्रा से पूर्ण करना अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त, नीति 2020-21 एवं देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की खुदरा बिक्री अनुज्ञापत्र की शर्तों तथा आबकारी आयुक्त के निर्देशों⁷ के अनुसार, देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा समूहों के अनुज्ञाधारी को मासिक ईपीए का न्यूनतम 30 प्रतिशत भाग 25 यूपी राजस्थान निर्मित मदिरा की उठाई गई मात्रा से तथा शेष 70 प्रतिशत भाग देशी मदिरा की उठाई गई मात्रा से पूरा करना था, जिसमें से न्यूनतम 40 प्रतिशत मात्रा 50/60 यूपी देशी मदिरा की होगी और अधिकतम 60 प्रतिशत मात्रा 5 यूपी से 40 यूपी देशी मदिरा की होनी चाहिए।

6 जिला आबकारी अधिकारी चूरु, धौलपुर, डूंगरपुर, जालोर (अगस्त 2022 से जनवरी 2023 के मध्य), बारां, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर (अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के मध्य)।

7 दिनांक 26 फरवरी 2020 और 23 फरवरी 2021

यदि अनुज्ञाधारी किसी माह विशेष में राजस्थान निर्मित मदिरा और 50/60 यूपी देशी मदिरा के निर्धारित गारंटी अनुपात को पूर्ण करने में असफल रहता है, तो उसे संबंधित तिमाही के अन्य महीनों में राजस्थान निर्मित मदिरा और 50/60 यूपी देशी मदिरा का उठाव इस प्रकार सुनिश्चित करना होगा कि तिमाही के लिए कुल त्रैमासिक ईपीए में राजस्थान निर्मित मदिरा और 50/60 यूपी देशी मदिरा की तिमाही गारंटी का कोटा पूर्ण हो सके। यदि किसी तिमाही में राजस्थान निर्मित मदिरा और 50/60 यूपी देशी मदिरा का उठाव निर्धारित कोटे से कम होता है तो अनुज्ञाधारी निर्धारित कोटा और वास्तविक उठाव के अंतर पर देय आबकारी शुल्क तथा बेसिक लाइसेंस शुल्क की राशि का भुगतान नकद में करने के लिये उत्तरदायी था।

सात जिला आबकारी अधिकारियों⁸ के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2019-21⁹ के दौरान 1,248 अनुज्ञाधारियों ने संबंधित तिमाहियों के लिए निर्धारित ₹ 341.09 करोड़ के कोटे के समक्ष ₹ 327.85 करोड़ मूल्य की 50/60 यूपी देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा का उठाव किया जिसके कारण 614 अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध तिमाही गारंटी कोटे में ₹ 13.24 करोड़ की कमी रही। इस कमी में से ₹ 1.44 करोड़ की राशि अनुज्ञाधारियों की जमानत राशि से वसूल/समायोजित की गई, तथापि, विभाग शेष ₹ 11.80 करोड़ की राशि 533 अनुज्ञाधारियों से वसूल नहीं कर सका। अतः नीति के प्रावधानों को लागू करने हेतु कार्रवाई नहीं करने के कारण ₹ 11.80 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2024)। सरकार ने (अगस्त 2024) जवाब दिया कि ₹ 0.58 करोड़ की वसूली/समायोजन कर लिया गया है तथा शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, जिला आबकारी अधिकारी धौलपुर के संबंध में यह कहा गया कि छः अनुज्ञाधारियों से ₹ 3.70 लाख की राशि वसूली योग्य नहीं है क्योंकि अनुज्ञापत्र की शर्तों में यह प्रावधान है कि प्रथम तिमाही में मदिरा के अधिक उठाव के समक्ष अनुज्ञाधारी को द्वितीय तिमाही में समायोजन दिया जा सकता है। जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नीति, अनुज्ञापत्र की शर्तों या आबकारी आयुक्त के निर्देशों में वर्ष की अन्य तिमाहियों में राजस्थान निर्मित मदिरा और 50/60 यूपी देशी मदिरा के निर्धारित त्रैमासिक गारंटी कोटे में कमी की प्रथम तिमाही में मदिरा के अतिरिक्त उठाव की राशि के समायोजन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये संबंधित समायोजन आदेशों में, समायोजन वस्तुतः विशेष वेंड फीस की कमी के संबंध में था, तिमाही गारंटी कोटे में 50/60 यूपी देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की कम उठाई गई मात्रा पर आबकारी शुल्क की अंतर राशि के समायोजन के संबंध में नहीं था। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

8 जिला आबकारी अधिकारी चूरु, धौलपुर, डूंगरपुर, जालोर (अगस्त 2022 से जनवरी 2023 के मध्य), बारां, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर (अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के मध्य)।

9 जिला आबकारी अधिकारी बारां, चूरु, डूंगरपुर (2019-20 और 2020-21), धौलपुर, जालोर, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर (2020-21)।

5.7 मदिरा दुकानों से कम्पोजिट फीस की कम वसूली

राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2021-22 के पैरा संख्या 4.2 तथा मदिरा दुकानों के अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन से संबंधित आबकारी आयुक्त द्वारा जारी विस्तृत निर्देशों एवं शर्तों के पैरा संख्या 17.4 के अनुसार, मदिरा दुकानों के अनुज्ञाधारियों को दुकान के लिए निर्धारित कम्पोजिट फीस¹⁰ का 50 प्रतिशत 31 मार्च 2021 तक या दुकान प्रारंभ होने से पहले, जो भी पहले हो, का भुगतान करना अनिवार्य था तथा शेष 50 प्रतिशत कम्पोजिट फीस का अगले तीन महीनों में भुगतान किया जाना था।

इसके अतिरिक्त, शेष 50 प्रतिशत कम्पोजिट फीस को बिना ब्याज जमा कराने की शिथिलता राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दी गई तथा इसे 17 जून 2021 के आदेश के माध्यम से 31 अगस्त 2021 तक और बाद में 5 फरवरी 2022 के आदेश के माध्यम से 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया।

चार जिला आबकारी अधिकारियों¹¹ के अधीन रिटेल अनुज्ञाधारियों की कम्पोजिट फीस से संबंधित वर्ष 2021-22 की अभिलेखों की लेखापरीक्षा (अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के मध्य) के दौरान यह पाया गया कि 1081 अनुज्ञाधारियों में से 229 अनुज्ञाधारियों ने अपनी निर्धारित कम्पोजिट फीस ₹ 8.10 करोड़ के समक्ष केवल ₹ 4.99 करोड़ की राशि जमा की और शेष कम्पोजिट फीस जमा किए बिना पूरे वर्ष 31 मार्च 2022 तक अपनी दुकानें संचालित करते रहे जिसके कारण 222 अनुज्ञाधारियों से ₹ 3.11 करोड़ की कम्पोजिट फीस की कम वसूली हुई। यह दर्शाता है कि विभाग ने शेष कम्पोजिट फीस की वसूली नहीं की और अनुज्ञाधारियों को उनकी दुकानों के संचालन में अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2024)। राज्य सरकार ने जवाब दिया (अगस्त 2024) कि ₹ 0.57 करोड़ की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

5.8 अवधिपार बीयर स्टॉक पर आबकारी शुल्क की अवसूली

राजस्थान आबकारी अधिनियम (अधिनियम) की धारा 28 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित या अनुज्ञापत्र प्राप्त किसी भी डिस्टिलरी ब्रेवरी या पोट-स्टिल में निर्मित किसी भी आबकारी शुल्क योग्य वस्तु पर आबकारी शुल्क लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान ब्रेवरी नियम, 1972 के नियम 15 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार किसी ब्रेवरी में संग्रहीत किसी भी बीयर के आग या चोरी या माप-तौल या किसी अन्य दुर्घटना या कारण से नष्ट होने, हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। नियमों के नियम 41 में यह प्रावधान है कि जब तक

10 कम्पोजिट फीस: यह शुल्क उन दुकानों पर लगाया जाता है जिन्हें सभी प्रकार की मदिरा जैसे देशी मदिरा, भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर विक्रय का अधिकार प्राप्त होता है।

11 जिला आबकारी अधिकारी बारां, सवाई माधोपुर, सीकर और श्रीगंगानगर।

अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत लगाए गए शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है या ब्रेवर द्वारा राज्य से बाहर बीयर के निर्यात हेतु बंध-पत्र (बॉन्ड) निष्पादित नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी बीयर को ब्रेवरी से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 की राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति के पैरा 4.9.12 के अनुसार राज्य में बीयर की आपूर्ति हेतु 'उपयोग से पहले उत्तम' की अवधि छः माह से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई थी, और मद्य क्रय नीति¹² के पैरा 7.2 के अनुसार, बॉटलिंग की तिथि/माह से 225 दिन से अधिक पुराना कोई भी बीयर स्टॉक राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि यह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है।

जिला आबकारी अधिकारी, बहरोड़ के क्षेत्राधिकार में आने वाली एक ब्रेवरी¹³ के वर्ष 2021-23 की अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (नवंबर 2023) के दौरान यह पाया गया कि संबंधित ब्रेवर, निर्मित बीयर के 31,990 केसों को निर्माण की तिथि/माह (मार्च 2022 से नवंबर 2022) से एक वर्ष के भीतर प्रेषित करने में असफल रहा, जिससे वह बीयर मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गई। अवधिपार बीयर पर देय आबकारी शुल्क का भुगतान ब्रेवर द्वारा नहीं किया गया और न ही विभाग द्वारा उस अवधिपार स्टॉक को नष्ट करने एवं संबंधित प्रावधानों के अनुसार आबकारी शुल्क की वसूली के लिए कोई कार्रवाई की गई।

इस प्रकार, अवधिपार बीयर स्टॉक पर आबकारी शुल्क का भुगतान न तो ब्रेवर द्वारा किया गया और न ही आबकारी विभाग द्वारा इसकी मांग की गई, परिणामस्वरूप ₹ 2.53 करोड़ की आबकारी शुल्क की वसूली नहीं हुई। इसके अलावा, विभाग द्वारा ऐसी बीयर को नष्ट करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण अवधिपार बीयर स्टॉक ब्रेवरी में अवरुद्ध रहा और ऐसी बीयर के उपयोग के कारण किसी भी प्रकार की अनहोनी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई एवं जुलाई 2024)। राज्य सरकार ने (जून 2024) जवाब दिया कि संबंधित इकाई वर्तमान में उत्पादन के लिए बंद है और वे अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं। तथापि, बकाया राशि जमा कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है (जून 2024) तथा शुल्क की वसूली/बीयर के निस्तारण से संबंधित कार्यवाही नोटिस के जवाब प्राप्त होने पर की जाएगी। राज्य सरकार ने आगे बताया (अगस्त 2024) कि संबंधित इकाई ने राजस्थान उच्च न्यायालय से वसूली पर स्थगन (जुलाई 2024) प्राप्त कर लिया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

5.9 अनुज्ञापत्र की शर्तों के उल्लंघन पर लगायी गयी शास्ति की अवसूली

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (अधिनियम) की धारा 34 (ग) एवं राजस्थान आबकारी नियम, 1956 (नियम) के नियम 76 (ग) के अनुसार, यदि कोई अनुज्ञाधारी या उसका सेवक

12 फरवरी 2021 में राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएसबीसीएल) द्वारा जारी।

13 जिला आबकारी अधिकारी बहरोड़ के अंतर्गत मैसर्स जीविया बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड, भिवाड़ी।

अनुज्ञापत्र की किसी शर्त का उल्लंघन करता है या अधिनियम अथवा इसके तहत जारी किसी अधिसूचना, आदेश या नियम का उल्लंघन करता है, तो अनुज्ञा प्रदान करने वाला प्राधिकारी उस अनुज्ञापत्र को निरस्त या निलंबित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 58 (ग) अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञापत्र की किसी भी शर्त के उल्लंघन में जानबूझकर किए गए कार्य या चूक के लिए शास्ति सहित प्रत्येक अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है और अधिनियम की धारा 70 आबकारी अधिकारियों को निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन अपराध का शमन करने के लिए अधिकृत करती है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति के क्रमशः पैरा संख्या 15 एवं 14 तथा मदिरा की दुकानों हेतु आवेदन के संबंध में जारी विस्तृत निर्देशों की शर्त संख्या 26 में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय करने और निर्धारित समयसीमा के पश्चात दुकान खोलने पर अनुज्ञापत्र के निलंबन/निरस्तीकरण का प्रावधान किया गया है क्योंकि यह अधिनियम की धारा 58 (ग) प्रावधानानुसार अनुज्ञा की शर्त का उल्लंघन है।

छ: जिला आबकारी अधिकारियों¹⁴ के अधीन पंजीकृत व शमन किये गये प्रकरणों की लेखापरीक्षा (अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के मध्य) के दौरान पाया गया कि वर्ष 2017-23 के दौरान कुल 1,649 प्रकरण धारा 58 (ग) के अंतर्गत दर्ज किए गए। इनमें से 1,566 प्रकरणों में आबकारी आयुक्त या संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा शास्ति/शमनीय राशि आरोपित कर शमन किया गया। इन प्रकरणों में शमन आदेशानुसार, यदि शमनीय राशि 15 दिनों के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो धारा 34 (ग) एवं नियम 76 (ग) के तहत अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्रवाई की जानी थी।

यह देखा गया कि इन 1,566 प्रकरणों में से केवल 1,339 प्रकरणों में ही शमनीय राशि जमा की गई, शेष 227 प्रकरणों में ₹ 74.73 लाख की राशि संबंधित अनुज्ञाधारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं कराई गई थी। संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों ने न तो बकाया राशि वसूल की और न ही शमन आदेशों में उल्लेखित शर्तों के अनुसार ऐसे अनुज्ञाधारियों के अनुज्ञापत्र निरस्त किए तथा अनुज्ञाधारियों को बिना शास्ति का भुगतान किए व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी। अधिकांश प्रकरण एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा बेचने और निर्धारित समय के पश्चात् दुकान खोलने से संबंधित थे।

यद्यपि विभाग द्वारा दर्ज प्रकरणों की प्रविष्टि आईईएमएस के 'ऑनलाइन एफआईआर पंजीकरण मॉड्यूल' में की गई थी एवं एफआईआर इसी ऑनलाइन मॉड्यूल से मुद्रित की गई, लेकिन प्रकरणों के निपटान के संबंध में आगे की कार्यवाही को इस मॉड्यूल में अद्यतन नहीं किया गया, जिससे विभागीय अधिकारियों की प्रकरणों के निपटान एवं राशि ₹ 74.73 लाख की शास्ति की वसूली पर नियंत्रण में कमी इंगित होती है।

14 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, बारां, सवाई माधोपुर, सीकर और श्रीगंगानगर।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2024)। सरकार ने (अगस्त 2024) जवाब दिया कि ₹ 8.15 लाख की वसूली की जा चुकी है तथा शेष राशि की वसूली हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

5.10 वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की वसूली का अभाव

राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2022-23 तथा मदिरा की रिटेल बिक्री हेतु कम्पोजिट दुकानों की अनुज्ञापत्रों की शर्तों के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए अनुज्ञाधारी की वार्षिक गारंटी राशि के 5 प्रतिशत के बराबर वार्षिक अनुज्ञा शुल्क निर्धारित किया गया था। मदिरा दुकानों के अनुज्ञाधारियों को 14 मार्च 2022 तक दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की 50 प्रतिशत राशि जमा करानी थी अथवा यदि दुकान का आवंटन ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से किया गया हो, तो यह राशि नीलामी की शर्तों में निर्धारित तिथि तक जमा करनी थी। शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित वर्ष की द्वितीय एवं तृतीय तिमाही में समान किशतों में करना था। यदि अनुज्ञाधारी वार्षिक गारंटी राशि के आधार पर निर्धारित तिमाही गारंटी राशि पूर्ण कर लेता है, तो वह वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की 50% राशि के समक्ष मदिरा का उठाव कर सकता था।

इसके अतिरिक्त, जनवरी 2023 में आबकारी आयुक्त द्वारा सभी जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि अनुज्ञाधारियों की तृतीय तिमाही तक की शेष वार्षिक अनुज्ञा शुल्क राशि नकद जमा करके या 15 फरवरी 2023 तक मदिरा का उठाव कर तक पूर्ण की जा सकती है।

छ: जिला आबकारी अधिकारियों¹⁵ के अधीन रिटेल अनुज्ञाधारियों से संबंधित वार्षिक अनुज्ञा शुल्क अभिलेखों की लेखापरीक्षा (अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के मध्य) के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2022-23 में 1,799 अनुज्ञाधारियों ने अपने निर्धारित वार्षिक अनुज्ञा शुल्क राशि ₹ 91.85 करोड़ के समक्ष ₹ 90.93 करोड़ वार्षिक अनुज्ञा शुल्क जमा कराया, जिसके कारण 51 अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध ₹ 0.92 करोड़ के वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की कमी रही। इसके अलावा, जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा द्वितीय एवं तृतीय तिमाही की जमा वार्षिक अनुज्ञा शुल्क किशतों में से ₹ 14.86 करोड़ अनुज्ञाधारियों को मदिरा उठाव हेतु जारी किए, जबकि संबंधित अनुज्ञाधारियों द्वारा ₹ 14.08 करोड़ मूल्य की ही मदिरा का उठाव किया गया, जिससे 78 अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध ₹ 0.78 करोड़ के वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की कमी रही। इस प्रकार कुल 129 अनुज्ञाधारियों के समक्ष ₹ 1.70 करोड़ वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की कमी रही। इस कमी में से ₹ 0.19 करोड़ की वसूली या समायोजन अनुज्ञाधारियों की जमानत राशि से किया गया। तथापि, विभाग 106 अनुज्ञाधारियों से शेष ₹ 1.51 करोड़ की वसूली नहीं कर सका।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2024)। सरकार ने जवाब

15 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, बारां, सवाई माधोपुर, सीकर और श्रीगंगानगर।

दिया (सितम्बर 2024) कि ₹ 0.14 करोड़ की वसूली की जा चुकी है एवं शेष राशि की वसूली हेतु संबंधित आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

5.11 मदिरा के वार्षिक गारंटी कोटा के कम उठाव पर आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस की कम वसूली

राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति (नीति) वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के अनुसार देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों के अनुज्ञापत्र ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से दुकानवार न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित करके अधिकतम मूल्य के अनुसार प्राप्त वार्षिक गारंटी राशि पर आवंटित किए गए थे। इन कम्पोजिट दुकानों के अनुज्ञाधारी, वार्षिक गारंटी राशि की राशि, आबकारी शुल्क एवं अतिरिक्त आबकारी शुल्क के रूप में भुगतान हेतु उत्तरदायी थी। इसके अलावा, नीति के विस्तृत निर्देशों और शर्तों¹⁶ में वर्ष 2021-22 के लिए मदिरा उठाव का अनुपात का प्रावधान किया गया है।

16 अनुज्ञाधारियों को देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की कुल वार्षिक गारंटी राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत राजस्थान निर्मित मदिरा की उठाई गई मात्रा से और शेष 50 प्रतिशत देशी मदिरा की उठाई गई मात्रा से पूर्ण करना था, जिसमें न्यूनतम 40 प्रतिशत 50/60 यूपी देशी मदिरा की उठाई गई मात्रा से तथा 60 प्रतिशत 40 यूपी देशी मदिरा से की गई मात्रा से पूरा करना था।

- यदि किसी माह विशेष में अनुज्ञाधारी द्वारा निर्धारित गारंटी अनुपात के अनुसार देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की उठाई गई मात्रा पूरी नहीं की जाती है, तो उसे संबंधित त्रैमासिक के अन्य महीनों में देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा का इस प्रकार उठाव सुनिश्चित करना था कि देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की कुल त्रैमासिक वार्षिक गारंटी राशि की 50 प्रतिशत गारंटी राजस्थान निर्मित मदिरा के आबकारी शुल्क से, 20 प्रतिशत गारंटी 50/60 यूपी देशी मदिरा से, तथा शेष 30 प्रतिशत गारंटी 5 यूपी से 40 यूपी तक की देशी मदिरा की मात्रा से पूरी की जानी थी।

- यदि निर्धारित अनुपात के अनुसार त्रैमासिक गारंटी राशि (त्रैमासिक एमआरपी के बराबर) के समक्ष मदिरा का कम उठाव किया है तो अनुज्ञाधारी को वांछित कोटा और वास्तविक उठाई गई मदिरा के आधार पर देय आबकारी शुल्क और बेसिक लाइसेंस फीस के अंतर की राशि नकद में जमा करनी थी।

- राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निर्मित मदिरा के उठाव में छूट दी गई थी, जिसके अंतर्गत अनुज्ञाधारियों के पास देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की कुल वार्षिक गारंटी राशि के 50 प्रतिशत के स्थान पर न्यूनतम 35 प्रतिशत को राजस्थान निर्मित मदिरा की उठाई गई मात्रा से तथा शेष 15 प्रतिशत देशी मदिरा (दिनांक 09 सितंबर 2021 से प्रभावी) या आईएमएफएल (दिनांक 02 दिसंबर 2021 से प्रभावी) की उठाई गई मात्रा से पूरा करने का विकल्प था। इसके अलावा, पहली तिमाही में मदिरा के अतिरिक्त उठाव को दूसरी और तीसरी तिमाही की कमी के समक्ष समायोजित करने की अनुमति दी गई तथा पहली और दूसरी तिमाही की कमी को तीसरी तिमाही में उठाव करके पूरा करने की छूट भी प्रदान की गई। इसके अलावा, सरकार द्वारा (दिनांक 28 मार्च 2022) यह छूट भी प्रदान की गई कि पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही की कमी को मार्च 2022 तक मदिरा के उठाव द्वारा पूरा किया जा सकता था।

इसी प्रकार, नीति और शर्तों¹⁷ में वर्ष 2022-23 के लिए मदिरा उठाव के अनुपात का प्रावधान किया गया है।

छ: जिला आबकारी अधिकारियों¹⁸ के कार्यालयों के अभिलेखों, ईपीए रिपोर्ट, और आईईएमएस (राज्य आबकारी विभाग की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली) से डाउनलोड किए गए दुकानों के गारंटी डाटा एवं जिला आबकारी अधिकारियों से प्राप्त जानकारी सहित लेखापरीक्षा (अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के मध्य) के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2021-23 के दौरान 2,885 अनुज्ञाधारियों ने संबंधित तिमाहियों के लिए निर्धारित ₹ 2,772.85 करोड़ के कोटे के समक्ष ₹ 2,566.19 करोड़ की मदिरा का ही उठाव किया, जिसके परिणामस्वरूप 1,744 अनुज्ञाधारियों की वार्षिक गारंटी राशि में ₹ 206.66 करोड़ की कमी रही। इस कमी में से ₹ 43.29 करोड़ की राशि अनुज्ञाधारियों की जमानत राशि से वसूल या समायोजित की गई। तथापि, विभाग 1,138 अनुज्ञाधारियों से शेष ₹ 163.37 करोड़ की गारंटी राशि की वसूली नहीं कर सका, जैसा कि नीचे दी गई तालिका 5.2 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 5.2: वार्षिक गारंटी राशि की वसूली में कमी

वर्ष	कुल अनुज्ञाधारी	निर्धारित कोटा (₹ करोड़ में)	उठाई गई मदिरा (₹ करोड़ में)	कमी राशि (₹ करोड़ में)	दोषी अनुज्ञाधारियों की संख्या	वसूल/समायोजित राशि (₹ करोड़ में)	शेष दोषी अनुज्ञाधारी	शेष राशि (₹ करोड़ में)
2021-22	1,086 (चार ¹⁹ जिला आबकारी अधिकारियों के अन्तर्गत के अंतर्गत)	951.85	803.90	147.95	937	35.97	665	111.98

17 अनुज्ञाधारियों को कुल देशी मदिरा (राजस्थान निर्मित मदिरा सहित) की वार्षिक गारंटी राशि की न्यूनतम 30 प्रतिशत राशि की पूर्ति राजस्थान निर्मित मदिरा की उठाई गयी मात्रा से तथा शेष 70 प्रतिशत वार्षिक गारंटी राशि की न्यूनतम 40 प्रतिशत राशि की पूर्ति 50/60 यूपी देशी मदिरा की उठाई गयी मात्रा से सुनिश्चित करनी थी।

- यदि कोई अनुज्ञाधारी किसी माह विशेष में उपर्युक्त निर्धारित गारंटी अनुपात की पूर्ति करने में विफल रहता है तो उसे संबंधित तिमाही के अन्य महीनों में इस प्रकार मदिरा का उठाव सुनिश्चित करना था कि कुल त्रैमासिक देशी मदिरा की वार्षिक गारंटी राशि (राजस्थान निर्मित मदिरा सहित) का 30 प्रतिशत राजस्थान निर्मित मदिरा पर लगने वाले आबकारी शुल्क से तथा 28 प्रतिशत गारंटी 50/60 यूपी देशी मदिरा से पूरी की जा सके।
- यदि त्रैमासिक गारंटी राशि (त्रैमासिक एमआरपी के बराबर) के निर्धारित अनुपात के समक्ष मदिरा के उठाव के मामले में अनुज्ञाधारी को वांछित कोटा और वास्तविक उठाव के बीच के अंतर की आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस नकद में जमा करानी थी।
- इसके अतिरिक्त, आबकारी आयुक्त (20 जुलाई 2022) द्वारा प्रथम त्रैमास की कमी को 30 जुलाई 2022 तक मदिरा उठाव कर पूरा करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही, आबकारी आयुक्त (30 जनवरी 2023) द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाही की कमी को 15 फरवरी 2023 तक मदिरा उठाव कर पूरा करने की छूट दी गई थी।

18 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, बारां, सवाई माधोपुर, सीकर और श्रीगंगानगर।

19 जिला आबकारी अधिकारी बारां, सवाई माधोपुर, सीकर और श्रीगंगानगर।

वर्ष	कुल अनुज्ञाधारी	निर्धारित कोटा (₹ करोड़ में)	उठाई गई मदिरा (₹ करोड़ में)	कमी राशि (₹ करोड़ में)	दोषी अनुज्ञाधारियों की संख्या	वसूल/समायोजित राशि (₹ करोड़ में)	शेष दोषी अनुज्ञाधारी	शेष राशि (₹ करोड़ में)
2022-23	1,799 (छ: 20 जिला आबकारी अधिकारियों के अन्तर्गत के अंतर्गत)	1,821.00	1,762.29	58.71	807	7.32	473	51.39
कुल	2885	2772.85	2566.19	206.66	1744	43.29	1138	163.37

इसके अतिरिक्त, ₹ 206.66 करोड़ की वार्षिक गारंटी राशि की कमी में ₹ 32.47 करोड़ की राजस्थान निर्मित मदिरा, ₹ 14.06 करोड़ की 50/60 यूपी देशी मदिरा और ₹ 41.55 करोड़ की 40 यूपी देशी मदिरा की कमी सम्मिलित थी जिस पर 1,487 अनुज्ञाधारियों से ₹ 45.55 करोड़ की बेसिक लाइसेंस फीस देय थी। इस कमी में से ₹ 2.13 करोड़ वसूल या जमानत राशि से समायोजित किये गये। तथापि, विभाग 1,073 अनुज्ञाधारियों से ₹ 43.42 करोड़ की शेष बेसिक लाइसेंस फीस की राशि की वसूली नहीं कर सका, जैसा कि नीचे दी गई तालिका 5.3 में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 5.3: बेसिक लाइसेंस फीस की वसूली में कमी

वर्ष	गारंटी राशि में कमी(निर्धारित कोटा और मदिरा उठाव के बीच का अंतर) (₹ करोड़ में)					राजस्थान निर्मित मदिरा और देशी मदिरा पर देय कुल बेसिक लाइसेंस फीस राशि। (₹ करोड़ में)	दोषी अनुज्ञाधारियों की संख्या	वसूल/समायोजित राशि (₹ करोड़ में)	शेष दोषी अनुज्ञाधारी	शेष बेसिक लाइसेंस फीस की राशि (₹ करोड़ में)
	कुल कमी	आईएमएफएल	आरएमएल	50/60 यूपी देशी मदिरा	40 यूपी देशी मदिरा					
2021-22	147.95	83.76	23.03	9.61	31.55	34.16	862	1.59	676	32.57
2022-23	58.71	34.82	09.44	4.45	10.00	11.39	625	0.54	397	10.85
कुल	206.66	118.58	32.47	14.06	41.55	45.55	1487	2.13	1073	43.42

अतः नीति और लाइसेंस की शर्तों के प्रावधानों को लागू करने में जिला आबकारी अधिकारियों की कार्यवाही की कमी के कारण ₹ 206.79 करोड़ की आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2024)। सरकार ने जवाब दिया (सितंबर 2024) कि ₹ 163.37 करोड़ के समक्ष ₹ 3.72 करोड़ गारंटी राशि तथा ₹ 43.42 करोड़ के समक्ष ₹ 0.55 करोड़ बेसिक लाइसेंस फीस की वसूली की जा चुकी है। यह भी बताया गया कि शेष राशि की वसूली हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

20 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, बारां, सवाई माधोपुर, सीकर और श्रीगंगानगर।